sector mill in Kalyani has been set up. Another mill is being set up for the West Bengal handloom weavers for the supply of yarn to handlooms.

Production and Price of Mill Cloth

+

*360. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Shree Narayan Das:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:
Shri P. C. Borooah:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Gulshan:
Shrimati Renuka Ray:
Shri Y. S. Chaudhary:
Shri B. K. Das:
Shri Dinen Bhattacharya:
Dr. Ranen Sen:
Dr. Saradish Roy:
Shrimati Jyotsna Chanda:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 129 on the 11th September, 1964 and state:

(a) the effective date on which statutory controls were introduced on the production and prices of popular varieties of mill cloth;

(b) whether the control has proved effective; and

(c) the organisational set up for exercising supervision over the working of the control?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3542/64).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्राय: देखा गया है कि सरकार जिन जिन चीजों का नियन्त्रण करती हैं वे वे चीजें बाजार से गायब हो जाती हैं । कपड़े के ऊपर भी जब नियन्त्रण किया जा रहा है, तो अच्छी किस्म का कपड़ा बाजार से गायब न हो जाए, इसके लिए भी कोई व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री मनुभाई शाह : इतना कपड़ा आज बाजार में मुहैया है होलसेल में और रिटेल में और मिलों में भी और उसके अलावा उत्पादन हैंडलूम सैक्टर का तथा पावरलूम सैक्टर का और मिलों का भी इतना बढ़ रहा है कि जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, उसका कोई कारण नहीं है :

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इसका भी आपने यत्न किया है कि अच्छा कपड़ा जिसका आपने नियन्त्रण किया है, इसके जो मूल्य हैं, उन्हीं मूल्यों पर बाजार में यह मिल सके, अधिक मूल्यों पर न मिले ? क्या इसकी देख रेख की भी कोई व्यवस्था आपने की है ?

श्री मनुभाई शाह : स्टटमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि पूरी व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था राज्य लेवल पर जिले के लेबल पर और गाव के लेबल पर कर दी गई है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती: मन्त्री महोदय ने फरमाया कि बहुत कपड़ा बन रहा है । लेकिन गांव के लोग जो कपड़ा पहनते हैं, उनके उपयोग का जो कपड़ा है, जैसे धोती है, पगड़ी का पकड़ा है, कुर्ते का कपड़ा है ....

एक माननीय सदस्य : लंगोटी है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : उन सब कपड़ों के दाम आपके कथनानुसार आसमान पर चढ़े हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन कपड़ों के दामों को कम करने का यत्न भी क्या आपकी तरफ से होगा ?

श्री मनुभाई शाह : इसी कपड़े को कण्ट्रोल में लाया गया है ।

श्री बागड़ी : मिलों में तैयार होने वाले कपड़े के दाम क्या उसी नीति पर तय किये गये हैं जिस नीति पर कि खाद्य पदार्थों के दाम जो किसान पैदा करता है, तय किये गये हैं ? क्या

मिलों में तैयार कपड़े के दाम ड्योढ़े से अधिक लागत मूल्य से न हों, इस आधार पर तय किये गये हैं और अगर नहीं किये गये हैं तो इसका कारण क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : सारी योजना मैंने सदन की मेज़ पर रखी है । पिछले तीन मास से जो इंडैक्स दिल्ली के अन्दर का रहा है तथा और जगहों पर के जो सरप्राइज़ इंडैक्स हैं, वे खुद बताते हैं कि मूल्यों में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है ।

श्री विभूति मिश्र : सेंट्रल क्लाथ कंज्यूमर्ज़ विजिलेंस कमेटी की जो प्रोपोजल्ज़ थीं ये क्या काम में आई हैं या नहीं आई हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुझाव दिये गये हैं इस कपड़े के बटवारे के सम्बन्ध में जिससे गांवों के लोगों के पास आसानी से कपड़ा पहुंच सके ?

श्री मनुभाई शाह : विजिलेंस कमेटी ने यह हिदायत की है कि राज्य स्तर पर और खास करके जिले के स्तर पर, जितने भी हिन्दुस्तान में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके स्तर पर पब्लिक कार्यकर्ताओं, ट्रेडर्ज़ और कंज्यूमर्ज़ की कमेटियां बनाई जाएं और वे बनाई जा रही हैं ताकि गांवों में या कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो फौरन वह सरकार के नोटिस में लाई जा सके ।

Shri P. C. Borooah: May I know, since the introduction of the control, whether some of the mills have slowed down the production of control cloth and, if so, to what extent the production has decreased and what steps have been taken against those mills which were responsible for slowing down the production?

Shri Manubhai Shah: The hon. Member knows that in the month of October there was a record production of cloth in the country, as has never happened in the past: 442 million yards.

श्री ओंकार लाल बेरवा : कपड़े पर जो नियन्त्रण लागू किया है इसमें मिल मालिकों को कितना प्राफिट मिलेगा और कंज्यूमर्ज़ के लिए क्या कुछ निश्चित किया गया है, इसका एनेलेसिस क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : कंज्यूमर्ज़ के रक्षण के लिए यह किया गया है । जहां तक कण्ट्रोल का ताल्लुक है, यह पुराने मिलों के दामों से कुछ कम है और मिलों को कुछ कम ही दाम मिलेंगे ।

श्री ओंकार लाल बेरवा: परसेंटेज प्राफिट क्या है ? नुकसान देकर तो वे बेचेंगे नहीं ।

श्री मनुभाई शाह : वह भी कायदे से नियत किया गया है कि 18 परसेंट से अधिक वितरण का प्राफिट न हो ।

Shri B. K. Das: May I know whether any of the mills have indicated their difficulties about switching over to the production of this controlled cloth?

Shri Manubhai Shah: Yes, Sir; there is production control by which Government directs that a particular mill shall produce so much of a particular variety and sometimes there are some difficulties.

श्री यु० सिं० चौधरी : देहातों में ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बांटने के बारे में जो बहुत सुन्दर बात सरकार ने कही है क्या उसके बारे में उसने प्रादेशिक सरकारों से परामर्श किया है, और क्या उनकी राय जान कर इस प्रकार की कमेटियों की स्थापना करने के लिये, जैसा कि श्री विभूति मिश्र के प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया, विधिवत् बात हो चुकी है ।

श्री मनुभाई शाह : हर राज्य की सरकार को हमने पत्र लिखे है और बहुत सी सरकारों ने तो यह कमेटियां नियुक्त भी कर दी हैं । जहां उनके नियुक्त करने में देर होगी वहां हम फिर अनुरोध करेंगे कि उन्हें बनाया जाये ।

Shri Dinen Bhattacharya: In the statement it is stated that for some

varieties, there has been reduction in price to the extent of 5 to 10 per cent and for certain varieties the cost has been increased to the extent of a certain percentage. May I ask what is the basis on which this percentage has been calculated?

Shri Manubhai Shah: There is a whole set of multipliers and special allowances based on technical grounds like amount of cotton, amount of processing and labour management charges, etc. 95 per cent of the cloth have shown a decline by 5 to 8 per cent. In the remaining 5 per cent of cloth which was produced in 1961 and whose prices had not at all been increased in the last four years, there has been a slight rise in price.

Shri P. Venkatasubbaiah: May I know whether Government is aware of the fact that soon after the promulgation of control on certain varieties of cloth, an artificial scarcity has been created in the market and that there is a general feeling among the people that they are suffering not only for want of food but also for want of required cloth?

Shri Manubhai Shah: This is the first time I hear from the hon. Member about it. Not a single newspaper in this country carries news of any scarcity of cloth. As a matter of fact, during the Diwali holidays, I had sent telegrams to the Chief Ministers. They said, "Why do you bother"? There is no question of any scarcity of cloth.

Shri S. M. Banerjee: From the statement it appears:

> "....the industry and trade were naturally holding large stocks of cloth produced before 20th October, 1964. It is expected that the old stocks of cloth of the five categories which are now under control will be sold out within two or three months."

May I know what was the stock which came into the market when controlled prices were imposed, after 20th October, 1964 and what steps have been taken to see that the stocks do not remain with the mill-owners?

Shri Manubhai Shah: There has been no machinery and there cannot be any machinery to find out how much cloth is there in retail and wholesale shops in this vast country. On an average looking to the traditions of the country, four to five months consumption of the country is always on the pipeline. There is no reason to believe that anything less than that was there.

Shri Ranga: What steps are being taken to ensure that a good percentage of the total cloth that is being produced would be of the utility variety, so that it would be within the capacity of the poorer folk to purchase?

Shri Manubhai Shah: We have taken utility as the criterion. The cloth that goes into mass consumption for the middle-class, lower middle-class and poor class, namely, dhotis, saris, cheaper and moderate-priced long cloth, shirting and drills have been brought under control.

श्री शिव नारायण : बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की सरकार सोच रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं . . .

श्री मनुभाई शाह : इसमें बार्टर कहां आता है, यह मुल्क के अन्दर की बात है ।

Dr. Saradish Roy: May I know whether the prices of medium and fine variety of cloth are going to be controlled?

Shri Manubhai Shah: The control has not been based on coarse, medium, fine or super-fine cloth. Dhotis, saris, long cloth, shirting and drills, whatever category they are made of, are brought under control.

Shri Daji: Is it a fact that the control prices are lower than the sale prices and in many cases higher than the prevailing market prices and that there is confusion between wholesale traders and mill-owners about a parti-

cular practice of about 1 per cent commission that was being given to the traders and so, there is a deadlock in many important cloth markets? May I know what is Government's policy in this regard?

Shri Manubhai Shah: This matter was brought to our notice in Indore, from where the hon. Member hails, that there was some old practice. But law and this kind of trade cannot take into account every local practice in this connection. Even then we are intervening to settle the difference of opinion between the traders and mill-owners in Indore.

श्री तुलशीदास जाधव : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने कपड़े की जरूरत होती है और जितना कपड़ा बाहर भेजना होता है, क्या उन दोनों की जरूरतें पूरी होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो जो लोग पावर लूम और ज्यादा लगाने के लिये तैयार हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन क्यों रक्खा गया है।

श्री मनुभाई शाह : हमने इस बात पर पूरी तरह पर गौर किया है। जितने कपड़े की जरूरत होती है, उससे ज्यादा कपड़ा यहां पर तैयार किया जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि फोर्थ प्लैन में लोगों का स्टैण्डर्ड ग्राफ लिविंग बढ़ने वाला है, इसलिये अशोक मेहता पावर लूम कमेटी इस पर गौर कर रही है। अगर ठीक समझा गया तो पावर लूम्स और ज्यादा हो जायेंगे।

GATT Conference

*361. **Shri P. C. Borooah:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) which of the industrialised countries have relaxed import duties on various items of export interest to the developing countries in pursuance of the resolution on the subject adopted at the recent GATT Conference and to what extent;

(b) the steps taken to increase the export of these items to those countries; and

(c) how far India's exports to those countries are likely to improve on account of these concessions?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) A list is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3543/64].

(b) A number of steps are being taken continuously for increasing India's exports and the concessions in import duties obtained pursuant to the resolution adopted in the GATT Conference will be helpful to these efforts.

(c) The duty concessions in question have been in effect for a short time only and it is too early to attempt any reasonable estimate of the extent of their beneficial effects on India's trade. But, Sir, I can say that even during these few months the benefits are obvious.

Shri P. C. Borooah: May I know whether in spite of GATT's policy resolution under reference, the British Government have recently imposed a surcharge on imports; if so, how far it is likely to affect India's exports and what was GATT's reaction to India's protest at their recent meeting at Brussels?

Shri Manubhai Shah: Sir, we are very much concerned with the recent surcharge imposed by the U.K. Government. While we have full sympathy with the difficulties they experience at the moment in regard to their foreign exchange balances, it will hit this country very hard and our loss estimated is about Rs. 10 crores per year if the present surcharge remains. We have made suitable representations and I am glad on our first representation itself East India kips and semi-tanned leather goods were removed from the duty and coir products, handloom products and hand-made carpets, which give a large amount of employment in the country, are being sympathetically considered by the British Government and the duties on these products, we